निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी 7.5 % की तैयारी

■ अजित खरे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश निर्यात के मामले में पूरे देश में अपनी हिस्सेदारी 7.5 प्रतिशत ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए योगी सरकार अगले पांच साल के लिए नई निर्यात नीति लाने जा रही है। इसके लिए निर्यात को पांच साल में तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा समुद्र तटीय वाले राज्यों के कारोबारियों के बराबर की सहूलियतें यूपी के निर्यातकों को देने की तैयारी है। सबसे फोकस निर्माण व सेवा क्षेत्र पर होगा। एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ बढ़ाने, कारोबारियों के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही निर्यातकों को विशेषज्ञों को पैनल बताएगा कि किस माल का निर्यात किस तरह किस देश को किया जाए। असल में राज्य की मौजूदा निर्यात नीति 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद अप्रैल 2025 से मार्च 2030 तक के लिए नई निर्यात नीति बनाई जा रही है। नई चुनौतियों, आवश्यकताओं व लक्ष्यों के चलते पुरानी नीति में कई बदलाव किए जा रहे हैं। अभी देश में यूपी की निर्यात की हिस्सेदारी 5.8 प्रतिशत है। मल्टीनेशनल कंपनियों को बड़ी जमीन उपलब्ध कराने के लिए अलीगढ़, उन्नाव व प्रयागराज- चित्रकूट में स्पेशल इकनॉमिक जोन में 80 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। यहां बड़ी कंपनियां इन प्लग एंड प्ले के साथ इन पार्कों में अपने उद्योग लगाएंगी।

नई निर्यात नीति के लिए निर्यातकों, कारोबारियों व अन्य स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे जा रहे हैं। नीति में माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग व शोध पर खास फोकस जाएगा ताकि गुणवत्ता बरकरार रहे ।

पवन अग्रवाल, संयुक्त निर्यात आयुक्त

निर्यात की स्थिति

वित्तीय वर्ष	निर्यात मूल्य करोड़ रुपये
2020-21	121139.94
2021-22	156897
2022 -23	174037.01
2023-24	170340.95
2024-25	87151.09

(सितंबर 2024 तक)